स्वास्थ्य के लक्ष्यों पर कायम रहे सरकार

भारत डोगरा

इस साल के बजट से एक बार फिर संकेत मिले हैं कि सरकार सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पंहुचाने के 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से पीछे हट रही है। यदि इस लक्ष्य को पटरी पर रखना होता तो स्वास्थ्य के बजट में बड़ी वृद्धि की ज़रूरत थी, पर इस बजट में मामूली वृद्धि ही हुई है, जो मुश्किल से मंहगाई के असर को दूर करने में ही सक्षम सिद्ध होगी। यह ऐसे समय किया गया है जब स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई पहल की बात कही जा रही है। बजट नहीं बढ़ेगा तो नई पहल कैसे होंगी?

जहां एक समय सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य पर खर्च के हिस्से को 12वीं योजना के दौरान 1.04 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक पंहुचाने की बात थी, वहां अब यह लक्ष्य 1.87 प्रतिशत ही रखा गया है। इस तक भी हम पहुंच सकेंगे कि नहीं? यह सवाल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष भी स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई थी। 2012-13 के मूल बजट में 34,388 करोड़ के प्रावधान को 29,273 करोड़ कर दिया गया था।

मुद्दा केवल सार्वजनिक खर्च में अपेक्षित वृद्धि का ही नहीं है। दवा कीमतों के असरदार नियंत्रण से भी लोगों को राहत मिल सकती है, पर इस संदर्भ में जनहित याचिका के बाद जारी किए गए आदेशों का भी सरकार सही पालन नहीं कर रही है व मुद्दे को उलझा रही है।

सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र को अनेक सुविधाएं दी हैं पर उसका उचित नियमन नहीं किया है। इस कारण कई अनैतिक प्रवृतियां तेज़ी से बढ़ी हैं। यहां तक कि सरकार की लोक-लुभावन बीमा योजनाओं के धन का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह सरकार निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता दे रही है और भारी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है, उससे तो यह सवाल उठता है कि जितना बजट बढ़ा है उसका लाभ भी ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व जननी सुरक्षा योजना शुरू होने के समय काफी उम्मीद जगी थी, पर अब यह उम्मीद धूमिल होती जा रही है क्योंकि मिशन के क्रियान्वयन में भी गंभीर भ्रष्टाचार सामने आया है। एक तो जितने संसाधन ज़रूरी हैं वे मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं उनका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

देश में करोड़ों लोग इस कारण गरीबी में धकेले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बीमारी से इलाज के लिए अवहनीय खर्च सहना पड़ता है। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां अवहनीय हद तक लोगों को अपने निजी स्तर पर स्वास्थ्य सम्बंधी खर्च करने की मजबूरी है। विश्व के अधिकांश देशों में यह ज़िम्मेदारी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संभाले जाने की प्रवृति स्पष्ट नज़र आती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में वास्तविक सुधार के लिए ज़रूरी है कि सरकार स्वास्थ्य का बजट काफी अधिक बढ़ाए और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख ज़िम्मेदारी संभाले। दूसरा ज़रूरी कदम है कि निजी क्षेत्र का उचित नियमन हो। तीसरा महत्त्वपूर्ण कदम यह है कि सभी ज़रूरी जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों का नियंत्रण असरदार ढंग से हो।

मूल बात यह है कि एक ओर तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों तथा दूसरी ओर इन संसाधनों पर मोटे मुनाफे की मार पर रोक लगे ताकि इन संसाधनों का उपयोग वास्तव में स्वास्थ्य सेवाएं व दवाएं सब तक पहुंचाने के लिए हो सके। ***(स्रोत फीचर्स)***